

सलमान खान ने 60वें जन्मदिन पर पनवेल फार्महाउस पर केक काटा, परिवार और मीडिया संग सेलिब्रेशन



मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपने 60वें जन्मदिन पर अपने पनवेल फार्महाउस पर सरल लेकिन खास अंदाज में केक काटा। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया और पपराज़ी के साथ केक काटा, तस्वीरों के लिए पोज दिए और प्रशंसकों को भी इस पल का आनंद लेने का मौका दिया।

सलमान की परिवार और करीबी दोस्त भी मौके पर शामिल रहे, जिनमें उनके भाई अलग-अलग सदस्य, बहन अर्पिता खान तथा उनके पति आयुष शर्मा और क्रिकेटर एमएस धोनी अपनी पत्नी एवं बेटी के साथ मौजूद थे। समारोह में सलमान के जीवन और करियर पर आधारित एक खास वीडियो ट्रिब्यूट भी दिखाया गया। सलमान का यह जन्मदिन पारंपरिक और निजी तरीके से मनाया गया, जिसमें इंडस्ट्री के चुनिंदा लोग और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। इस दिन बांद्रा-वर्ली सी लिंक को भी रोशन कर सलमान के सम्मान में खास lights-up किया गया है।

'सिर्फ अल्लाह और जनता के प्रति जवाबदेह...' हुर्रियत चेयरमैन पदनाम हटाने पर बोले मीरवाइज फारूकी



संवाददाता |

श्रीनगर: कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु और अलगाववादी समूह ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (APHC) के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक ने अपने X (पूर्व ट्विटर) प्रोफाइल से 'हुर्रियत सम्मेलन के अध्यक्ष' का पदनाम हटा दिया है। उन्होंने इस बदलाव को अधिकारियों के दबाव के तहत मजबूरी में लिया गया निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने पदनाम न हटाया तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया जा सकता था। इसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया क्योंकि यह प्लेटफॉर्म उनके पास लोगों से संवाद करने का “बहुत कम उपलब्ध साधन” है।

APHC के कई घटक संगठन और फारूक

के अपने संगठन आवामी एक्शन कमिटी को अप्राकृतिक गतिविधियों (निषेध) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे उन्हें पदनाम हटाने का दबाव महसूस हुआ। फारूक ने अपने X बायो में अब केवल अपना नाम और स्थान दर्शाया है। इस कदम ने कश्मीर घाटी में अलगाववादी राजनीति और हुर्रियत की भूमिका पर नई चर्चाओं को जन्म दिया है। विरोधियों और विश्लेषकों का कहना है कि यह बदलाव हुर्रियत की गिरती प्रभावशीलता और राजनीतिक भूमिका में बदलती वास्तविकता का संकेत देता है। हालांकि फारूक ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ एक तकनीकी परिवर्तन था, न कि किसी विचारवादी बदलाव का संकेत।

उन्नाव दुष्कर्म कांड: कुलदीप सेंगर की बढ़ेंगी मुश्किलें, हाईकोर्ट के फैसले को CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पीटीआई, नई दिल्ली। सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव दुष्कर्म कांड में निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अप्रकट की सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के बाद विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के जरिये फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि वह दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में 10 साल की सजा भी साथ में भुगत रहा है।

पूर्व विधायक ने उग्र कैद की सजा के खिलाफ अपील की थी, जिसका सीबीआई और पीड़िता के स्वजनों ने जोरदार तरीके से विरोध किया था। सीबीआई की तरफ से जारी बयान के मुताबिक

एजेंसी ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलीलें दाखिल कीं।

पीडित परिवार ने भी सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा इस आधार पर निलंबित की कि दोषी इस मामले में सात साल और पांच महीने की सजा पहले ही भुगत चुका है।

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील लंबित रहने तक सेंगर की सजा मंगलवार को निलंबित की गई थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के दिसंबर 2019 के फैसले को चुनौती दी है।

सेंगर को 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को उत्तर प्रदेश की ट्रायल कोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया था।

NEWS DELHI | 20 होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया

नई दिल्ली | शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करने का भव्य समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देशभर के 20 बच्चों को वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला-संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार विजेताओं के चेहरे पर गर्व और खुशी स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इन बच्चों ने न सिर्फ अपने परिवार और समुदाय का गौरव बढ़ाया है, बल्कि पूरे देश को भी प्रेरित किया है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में विश्वास जताया कि यह



सम्मान अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और उन्हें उत्कृष्टता की ओर अप्रसर करेगा। उन्होंने वीर बाल दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि लगभग 320 साल पहले दसवें सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके चार पुत्रों ने सत्य एवं न्याय की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था।

मुर्मू ने विशेष रूप से दो सबसे कम उम्र के साहिबज़ादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि दी और कहा कि ऐसे वीर बाल नायकों की कहानी देश के हर नागरिक को प्रेरित करती है।

पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं: बहादुरी: व्योमा प्रिया (मरणोपरांत), कमलेश कुमार

(मरणोपरांत), अजय राज, मोहम्मद सिदान पी। खेल: वैभव सूर्यवंशी, ज्योशना साबर, डी. दिसिंधु, शिवानी होसुरु उप्पारा, योगिता मंडावी, ज्योति। इनोवेटर एवं स्कॉलर्स: रिशिक कुमार, श्रवण सिंह, अनीश सरकार, वी. लक्ष्मी प्रगनिका, आइशी प्रिशा बोरा, पूजा पाल, अर्णव महर्षि, एस्तेर लालदुहावमी हनामते।

यह पुरस्कार भारत के युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दिया जाता है ताकि वे आगे बढ़ कर देश के विकास और समाज की सेवा में अपना योगदान दे सकें। राष्ट्रपति ने सभी सम्मानित बच्चों को भविष्य की उज्ज्वल उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दीं और कहा कि देश को अपने युवा पर गर्व है।



सरकार का फ़रमान: ललित मोदी-विजय माल्या जैसे भगोड़ों को वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध – विदेशी मंत्रालय

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (MEA) ने ललित मोदी और विजय माल्या के एक वायरल वीडियो के बाद स्पष्ट कर दिया है कि भारत सरकार उन सब भगोड़ों को देश वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो कानून से बचकर विदेश में हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के जरिए ऐसे व्यक्तियों को भारत ला रही है ताकि वे यहाँ न्याय के सामने मुकदमे का सामना कर सकें।

यह बयान उस वीडियो के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें ललित मोदी ने लंदन में विजय माल्या के साथ पार्टी का क्लिप पोस्ट किया था और खुद को तथा माल्या को “भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े” कहते हुए देखा गया। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएँ और आलोचना उत्पन्न की थी। MEA ने कहा कि कई देशों के साथ बातचीत जारी है और

कानूनी प्रक्रियाएं समय ले रही हैं, लेकिन सरकार का फ़ैसला स्पष्ट है कि जो भी कानून से भागे हैं उन्हें वापस लाकर न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।

ललित मोदी और विजय माल्या दोनों पर भारत में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोप हैं और वे कई वर्षों से विदेश में रह रहे हैं, जिससे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया कानूनी जटिलताओं के कारण लंबित है।

विदर्भ में महायुति गठबंधन तय: चार महापालिकाओं में शिंदे सेना-भाजपा साथ, दो में अजित पवार की एनसीपी शामिल



विदर्भ (महाराष्ट्र): आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए महायुति (महाराष्ट्र विकास अघाड़ी-मूल पक्ष से अलग भाजपा-शिंदे सेना एनसीपी-अजित पवार गठबंधन) की रूपरेखा विदर्भ क्षेत्र में तय हो गई है। भाजपा ने स्थानीय निकायों में गठबंधन के लिए चार महापालिकाओं-नागपुर, चंद्रपूर, अकोला और अमरावती में शिंदे सेना के साथ मिलकर साझा झण्डे तले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वहीं **दो महापालिकाओं में भाजपा ने अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को महायुति में शामिल करने का निर्णय किया है।

सूत्रों के अनुसार चंद्रपूर और अकोला महापालिकाओं में एनसीपी (अजित

पवार) को महायुति गठबंधन का साझीदार बनाया गया है, जबकि नागपुर और अमरावती में भाजपा-शिंदे सेना मुख्य गठबंधन के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेगी। अमरावती में भाजपा-शिंदे सेना के साथ युवा स्वाभिमानी पार्टी के भी शामिल होने की संभावनाएं हैं।

यह कदम स्थानीय निकाय चुनावों में वोट बैंक और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। विदर्भ में महायुति के साझा मैदान में उतरने से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को सत्ता की चुनौतियों से निपटने में रणनीतिक मजबूती मिलने का प्रयास माना जा रहा है। वहीं, सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार चयन पर अभी अंतिम निर्णय बाकी है, जिसे आगे की बैठकों में तय किया जाएगा। यह राजनीतिक गठबंधन नागपुर-अकोला-चंद्रपूर-अमरावती सहित विदर्भ की महापालिका राजनीति को प्रभावित करेगा और आगामी चुनाव परिणामों में इसका अहम योगदान देखने को मिल सकता है।



क्रिसमस के दौरान तोड़फोड़ की पूर्व प्रधानमंत्री ने की निंदा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार

एएनआई, नई दिल्ली। कई राज्यों में क्रिसमस समारोह के दौरान तोड़फोड़ और हमलों की घटनाओं की पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने निंदा की। उन्होंने ऐसे कृत्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने दिल्ली में क्रिसमस प्रार्थना सभा में शामिल होने और ईसाई धर्म के प्रति सम्मान दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की। असम के नलबाड़ी में सेंट मैरी इंग्लिश

स्कूल में तोड़फोड़ के सिलसिले में पुलिस ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा सहित कई राज्यों में ईसाई समुदायों ने क्रिसमस समारोह के दौरान तोड़फोड़, धमकी और उत्पीड़न की शिकायत मिली थीं। उपद्रवियों पर सख्त

कार्रवाई होगी: हिमंता असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार शांति और संप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नलबाड़ी जिले के बेलसोर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पनीगांव स्थित सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल में हुई तोड़फोड़ में शामिल उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। असम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।



आतंकवाद से निपटने में ATS की भूमिका अहम, अमित शाह बोले पुलिस के लिए एक समान एंटी-टेररिस्ट स्कवॉड ढांचे की जरूरत

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में ' एंटी-टेररिज्म कॉन्फ्रेंस-2025 ' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देशभर में पुलिस के लिए एक समान एंटी-टेररिस्ट स्कवॉड (ATS) ढांचे की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही कहा कि आतंकवाद से निपटने में ATS की भूमिका बेहद अहम है और सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को इसे जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है: शाह न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि आज के दौर में आतंकवाद का स्वरूप बदल चुका है, जिसमें साइबर और सूचना युद्ध,

आर्थिक नेटवर्क का दुरुपयोग और हाइब्रिड आतंकवाद शामिल है। ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड विकसित करना जरूरी है, जो सतर्क हो और तेज व परिणामोन्मुख कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था ऐसे समेलनों के जरिए ही मजबूत हो सकती है। 'नीड टू नो' की जगह 'ड्यूटी टू शेयर' की अपील गृह मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में देश को सुरक्षित रखने के लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा मॉडल बनाना और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रवैया अपनाना जरूरी है। उन्होंने 'नीड टू नो' की जगह 'ड्यूटी टू शेयर' के सिद्धांत

पर काम करने की अपील की। अमित शाह ने यह भी कहा कि केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस ने अपने-अपने स्तर पर तकनीक का अच्छा उपयोग किया है, लेकिन अलग-अलग स्तर पर विकसित तकनीक और अलग-अलग जगह जमा किया गया डेटा ऐसा है जैसे बिना गोलियों की बंदूक। उन्होंने कहा कि अगर सभी डेटा एक-दूसरे से जुड़े और एक जैसी तकनीक पर आधारित हों, तो सुरक्षा तंत्र कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्रालय, एनआईए और आईबी को आपस में चर्चा कर एक सुचारू राष्ट्रीय तकनीकी और डेटा ढांचा विकसित करने तथा राज्यों को इसे मजबूत करने में सहयोग देने के निर्देश दिए।



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s unchanged.

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा : मानवाधिकार और क्षेत्रीय स्थिरता की गंभीर चुनौती

संपादकीय... |

बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हाल के दिनों में सामने आई हिंसक घटनाओं ने पूरे दक्षिण एशिया को चिंतित किया है। यह विषय अब केवल एक आंतरिक कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है, बल्कि मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन चुका है।

26 दिसंबर 2025 को प्रकाशित समाचारों के अनुसार, भारत सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ लगातार हो रही शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को “अनदेखा नहीं किया जा सकता।” यह बयान राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित हुआ।

समाचार एजेंसियों के मुताबिक, 18 दिसंबर 2025 को म्यमेंसिंग जिले में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या की गई। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया। इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला मौब हिंसा के सबसे क्रूर उदाहरणों में गिना जा रहा है। इसी अवधि में एक अन्य हिंदू नागरिक की मौत की भी खबरें सामने आईं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल गहरा गया।

26 दिसंबर 2025 को समाचार एजेंसी पीटीआई और ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि अंतरिम सरकार के कार्यकाल में बांग्लादेश में करीब 2,900 हिंसा-सम्बन्धी घटनाएँ दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें हिंदू, ईसाई और बौद्ध समुदाय प्रभावित हुए हैं। भारत सरकार ने इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई है।

वहीं, बांग्लादेश सरकार और वहां के पुलिस प्रशासन का पक्ष भी समाचारों में सामने आया है। 25 दिसंबर 2025 को ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेशी पुलिस का कहना है कि कई घटनाओं की पृष्ठभूमि राजनीतिक संघर्ष से जुड़ी है और सभी मामलों को सांप्रदायिक हिंसा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह तर्क स्थिति की जटिलता को दर्शाता है, लेकिन इससे पीड़ित समुदायों की पीड़ा कम नहीं होती।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित करती है। 26 दिसंबर 2025 को ‘अमर उजाला’ और ‘राज एक्सप्रेस’ में प्रकाशित समाचारों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और सरकार से कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है। अमेरिका और कनाडा के कुछ सांसदों ने भी हिंसा की घटनाओं की निंदा करते हुए मानवाधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया है।

भारत और बांग्लादेश के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें न केवल द्विपक्षीय रिश्तों पर असर डालती हैं, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी चुनौती बनती हैं। भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, लेकिन मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे सार्वभौमिक मूल्यों पर चुप भी नहीं रह सकती।

संपादकीय दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस मुद्दे को भावनात्मक उत्तेजना के बजाय तथ्यों और संतुलन के साथ देखा जाए। हिंसा चाहे राजनीतिक हो या सांप्रदायिक, उसका सबसे बड़ा शिकार आम नागरिक ही होता है। यदि किसी समुदाय को उसकी धार्मिक पहचान के कारण भय के वातावरण में जीना पड़े, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चेतावनी है।

अंततः, बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और दोषियों को बिना किसी भेदभाव के कानून के दायरे में लाए। वहीं, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देश के रूप में भारत की भूमिका यह सुनिश्चित करने की है कि संवाद, कूटनीति और मानवीय मूल्यों के माध्यम से स्थिति को सुधारा जाए।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा की घटनाएँ हमें याद दिलाती हैं कि धार्मिक सहिष्णुता, कानून का राज और मानवाधिकार केवल शब्द नहीं, बल्कि किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला हैं। इन्हें कमजोर होने देना पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

WORLD NEWS | Syria Bomb Blast: सीरिया के होम्स शहर में शुक्रवार को नमाज़ के दौरान मस्जिद में भीषण बम धमाका

नमाज़ के दौरान सीरिया की मस्जिद में भीषण बम धमाका, 8 लोगों की मौत, 18 घायल

दमस्कस: सीरिया के होम्स शहर में शुक्रवार को नमाज़ के दौरान एक मस्जिद में भीषण बम धमाका हुआ है। इस बम धमाके में अभी 8 लोगों की मौत और कम से कम 18 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि यह धमाका एक ऐसी मस्जिद में हुआ जो मुख्य रूप से अलावी इलाके में है और ये एक अल्पसंख्यक समुदाय की मस्जिद है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना ने रिपोर्ट दी है कि यह धमाका होम्स शहर के "वादी अल-दहाब इलाके में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के अंदर" हुआ। एजेंसी ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इस हमले में कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं।

न्यूज़ एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के गृह मंत्रालय ने इस घटना को "आतंकवादी धमाका" बताते हुए कहा कि शुक्रवार की नमाज़ के दौरान मस्जिद को निशाना बनाया गया है।



अल जज़ीरा के मुताबिक, यह मस्जिद इस्लाम के अलावी संप्रदाय से जुड़ी है, जो सीरिया की ज़्यादातर मुस्लिम आबादी में एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है। यह हमला मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली सीरियाई विद्रोही सेनाओं द्वारा दमिश्क पर कब्ज़ा करने के एक साल बाद हुआ है। शरा ने बशर अल-असद को सत्ता से हटा दिया था, जो अलावी

संप्रदाय के थे और पिछले साल अपनी सरकार गिरने के बाद रूस भाग गए थे। सीरिया की सरकार ने कहा आतंकी हमला पिछले एक साल में सीरियाई सुरक्षा बलों ने पूर्व सरकार के प्रति वफादार अलावी मिलिशिया से लड़ाई लड़ी है, लेकिन सीरिया में बड़ा समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक इस्लामिक स्टेट समूह (IS) के हमलों का शिकार हो रहे हैं।

यह समूह 2014 में सीरिया और इराक में "खलीफा" स्थापित करने की कोशिश के बाद 2017 में पूरी तरह से हार गया था, लेकिन इसके छोटे-मोटे बचे हुए गुट फिर से इकट्ठा हो गए हैं और देश में काम कर रहे हैं।

असद की सरकार के गिरने के बाद से, IS ने शरा के नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। ये लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहा है। आपको बता दें कि सीरियाई गृहयुद्ध 2011 में शुरू हुआ जब असद के प्रति वफादार सरकारी बलों ने उनके शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से दबाने की कोशिश की थी। 13 साल से ज्यादा के संघर्ष में, देश की आधी आबादी विस्थापित हो गई, लाखों सीरियाई तुर्की, यूरोप और आस-पास के अरब देशों में भाग गए। मरने वालों की संख्या, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन माना जाता है कि यह आधे मिलियन से ज्यादा सीरियाई लोगों की है।

नेपाल में क्या फिर से लौटेगी राजशाही और बनेगा हिंदू राष्ट्र? जिंदा हुई बहस, एक्सपर्ट से समझें

NEWS AGENCY

डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, काठमांडू: भारत का पड़ोसी देश नेपाल जेन-जेड तख्तापलट के बाद फिर से लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मार्च 2026 में आम चुनाव प्रस्तावित है। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने पहली बार वर्तमान पीएम सुशीला कार्की से मुलाकात की है। नेपाल में अब चुनावी तैयारी तेज होती जा रही है। लेकिन नेपाल आज कई गहरे राजनीतिक प्रश्नों से जूझ रहा है। क्या नेपाल के आमजनमानस का राजशाही में फिर से विश्वास लौट रहा है? क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? हाल ही में दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री बाबू राम भट्टराई कहा कि आज दोनों ही सवाल अप्रासंगिक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल कभी भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगा और राजशाही 'एक मृत शरीर है जिसे फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता।' भट्टराई के इस विश्वास के पीछे दशकों के माओवादी खूनी संघर्ष और गृह युद्ध के बाद निर्मित साल 2015 का संविधान है। इस संविधान द्वारा नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय और गणतांत्रिक राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है।

नेपाली नेता के दावे विपरीत हिमालयी देश में जमीनी हकीकत एवं तस्वीरें कुछ और अधिक जटिलता को बयां करती हैं। एक दशक लंबा माओवादी विद्रोह (1996-2006) और साल 2001 का शाही नरसंहार 1990 के बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर रहा है। किसी भी प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकना, साथ ही नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अवसरवादी गठबंधन और आर्थिक दुर्दशा ने आम लोगों का भरोसा राजनीतिक दलों से हिला दिया है। यही मोहभंग आज राजशाही और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को फिर से वैध राजनीतिक बहस का हिस्सा बना रहा है। नेपाल का साल 2015 का संविधान सामाजिक समावेश, धर्मनिरपेक्षता और शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतीक माना गया।



नेपाल के राजनीतिक असंतोष ने युवाओं को ऊर्जा दी

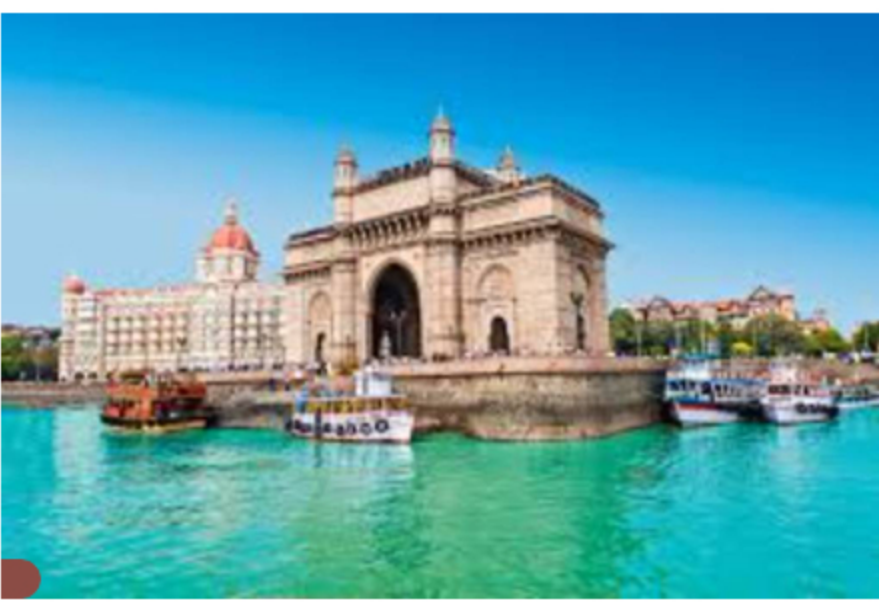
संघीय ढांचा और समानुपातिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए। लेकिन आज नेपाल के एक बड़े वर्ग को लगता है कि इन 'लोकतांत्रिक' व्यवस्थाओं ने नई तरह के अभिजात्य वर्ग की सौदेबाजी को ही जन्म दिया है। इसका नतीजा रहा कि Nepokids के खिलाफ युवाओं का गुस्सा फूट गया। चरमराती अर्थव्यवस्था पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रही। लाखों युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं। सरकारें बार-बार बदलती हैं, विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव अलग एजेंडे पर लड़ते तो हैं लेकिन चुनाव बाद विचारधारा को त्याग कर गठजोड़ कर सरकार बना लेते हैं। इसका परिणाम रहा कि लोक कल्याण की नीतियां लागू ही नहीं हो सकीं, अर्थव्यवस्था पटरी पर ही नहीं आ सकी। ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप लगभग हर दल और सत्ता-साझेदारी के हर मॉडल का पीछा करते दिखाई देते हैं। नेपाल में व्यापक राजनीतिक असंतोष ने युवाओं को एक विस्फोटक ऊर्जा दे दी। युवाओं ने स्पष्ट कर दिया कि नई पीढ़ी लोकतांत्रिक सत्ता के प्रतिष्ठान से बुरी तरीके से निराश हो चुकी है और अब उसे केवल चुनावों से परे वास्तविक बदलाव चाहिए। अपने जीवन की गुणवत्ता में बदलाव चाहिए।

नेपाल में राजनीतिक दलों के प्रति बढ़ता अविश्वास नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दलों पर सुशासन, आंतरिक लोकतंत्र और नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं।

नेतृत्व अब भी सीमित व्यक्तित्वों के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है और अवसरवादी गठबंधन धीरे-धीरे नेपाल की राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बनते गए हैं। नेपाल के पारंपरिक राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा-यूएमएल, माओवादी केंद्र और अन्य आम नेपाली की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे। आज आम नेपाली यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या यही संस्थाएं स्वयं को और देश की स्थिति की सुधारने में सक्षम हैं।

हिंदू राष्ट्र का नेपाल में क्यों बढ़ रहा आकर्षण?

हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले समूहों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता जनता की सहमति के बिना थोप दी गई और इससे नेपाल की पारंपरिक सांस्कृतिक पहचान कमजोर हुई। उनके लिए हिंदू राष्ट्र का अर्थ धार्मिक वर्चस्व से अधिक सांस्कृतिक आत्मगौरव है। इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ठोस परिणाम नहीं दे पाती, तब पहचान-आधारित राजनीति स्वाभाविक रूप से मज़बूत होती है। हाल के वर्षों में राजशाही समर्थक रैलियां कई हिस्सों में दिखने लगी हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि राजशाही के दौर में व्यवस्था और अनुशासन बेहतर थे। भले ही यह धारणा पूरी तरह वास्तविक न भी रही हो। वास्तव में यह समर्थन मौजूदा राजनीतिक मोहभंग का प्रतिबिंब है। जब वर्तमान बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था भरोसा पैदा नहीं कर सकी तब लोक अतीत को एक सुरक्षित विकल्प की तरह याद करने लगे हैं।



महाराष्ट्र विशेष

कोकण > पश्चिम महाराष्ट्र > मराठवाड़ा > विदर्भ



नंदिग्राम टाइम्स

Saturday 27th December 2025 वर्ष - 9 , अंक 241 , पृष्ठ 03



बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बीकेसी में बुलेट ट्रेन का काम रुका, बीएमसी ने लगाई रोक

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में चल रहे मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। बीएमसी द्वारा किए गए निरीक्षण में वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

अनुसार, साइट पर बैरिकेड की ऊंचाई तय मानकों से कम पाई गई, एयर-क्वालिटी मॉनिटरिंग उपकरण समय पर नहीं लगाए गए, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन खुले थे और अंदरूनी सड़कों पर पानी के स्प्रेकलर की व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा मलबे के निपटान में भी लापरवाही देखी गई।

बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि जब तक धूल और वायु प्रदूषण रोकने से जुड़े सभी

नियम पूरी तरह लागू नहीं किए जाते, तब तक खुदाई और मिट्टी हटाने सहित सभी निर्माण गतिविधियां बंद रहेंगी। यह प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा संचालित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई थी।

BMC ELECTION | मुंबई बीएमसी चुनाव में योगी के 'बंटोगे तो कटोगे' का नया वर्जन,

मुंबई बीएमसी चुनाव में 'बंटोगे तो पिटोगे' का सियासी शोर, बीजेपी-मनसे आमने-सामने, मराठी-हिंदी विवाद तेज

मुंबई | मुंबई: मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी तापमान बढ़ गया है। चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चर्चित नारे 'बंटोगे तो कटोगे' का नया और विवादित रूप सामने आया है। इस बार मुंबई की राजनीति में 'बंटोगे तो पिटोगे' नारा चर्चा के केंद्र में है, जिसने मराठी बनाम हिंदी भाषी विवाद को और हवा दे दी है।

पिछले विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ के नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "एक हैं तो सेफ हैं" के संदेश ने चुनावी माहौल को प्रभावित किया था। अब करीब साढ़े तीन साल बाद हो रहे बीएमसी चुनावों में वही सियासी रणनीति नए रूप में दिखाई दे रही है। हाल ही में मुंबई में लगाए गए एक विवादित बैनर, जिसमें उत्तर भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक संदेश लिखा गया था, ने इस पूरे विवाद को जन्म दिया।



ठाकरे बंधुओं (राज और उद्धव ठाकरे) के करीब आने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) और अधिक आक्रामक नजर आ रही है। मनसे नेताओं ने भाजपा पर मराठी और उत्तर भारतीय समुदायों को बांटने का आरोप लगाया है। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि मराठी लोगों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि

यह विवाद मराठी बनाम हिंदी भाषी का नहीं है, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर पैदा किया जा रहा है।

इस विवाद में शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता संजय राउत ने भी भाजपा और शिंदे गुट पर निशाना साधा। राउत ने आरोप लगाया कि हिंदी भाषियों और मराठी लोगों के बीच तनाव पैदा करने की साजिश की जा रही है।

उन्होंने भाजपा विधायक द्वारा एक मराठी रिकवा चालक के साथ मारपीट का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि क्या गरीब मराठी भाषियों पर हमला करना भाजपा की नीति है।

वहीं, शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने मनसे की चेतावनी को भड़काऊ बताते हुए मुंबई पुलिस से इस पर सज्जन लेने की मांग की। भाजपा मीडिया सेल प्रमुख नवनाथ बन ने कहा कि पार्टी समाज में तनाव फैलाने वालों का समर्थन नहीं करती और कुछ दल हार के डर से भाषाई विवाद खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता नसीम खान ने आरोप लगाया कि भाजपा हर चुनाव में सांप्रदायिकता और प्रांतवाद के मुद्दे उठाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या 'बंटोगे तो पिटोगे' जैसा नारा मुंबई बीएमसी चुनावों का टर्निंग प्वाइंट बनेगा। मुंबई में 15 जनवरी को मतदान होगा, जबकि नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे।

वाशिम: नगराध्यक्ष चुनाव हार के बाद पति की भावनात्मक पोस्ट के अगले दिन हुआ दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसा, हरीश हेडा की मौत



संवाददाता |

वाशिम (महाराष्ट्र): नगरपरिषद चुनाव में नगराध्यक्ष पद के लिए अपक्ष उम्मीदवार अलका हरीश हेडा को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक फेसबुक पोस्ट साझा कर अपनी हार की पीड़ा और मतदाताओं के प्रति आभार जताया।

लेकिन अगले ही दिन एक भयानक सड़क हादसा में उनके पति हरीश हेडा की मौत हो गई। हादसा कारंजा शहर के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहाँ तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने हरीश की दुचाकी को टक्कर मार दी, जिससे वे जागह पर ही गंभीर रूप से घायल होकर

दम तोड़ बैठे। हरीश हेडा स्थानीय मनसे नेता थे और चुनाव में अपनी पत्नी का समर्थन कर रहे थे। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिवार और पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने हादसे पर दुःख जताया है और प्रशासन से सड़क सुरक्षा पर कड़े कदम उठाने की मांग की है।

पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है और चालक को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। इस दुखद घटना ने एक राजनीतिक चुनौती के बाद व्यक्तिगत त्रासद क्षण को जन्म दिया है, जिससे परिजन और समर्थक गहरे सदमे में हैं।

महाराष्ट्र राजकारण में बड़ा बदलाव: NCP (SP) नेता प्रशांत जगताप ने कांग्रेस का दामन थामा

मुंबई/पुणे: महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना सामने आई है। प्रशांत जगताप, जो कि शरद पवार नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) के पुणे शहर अध्यक्ष और पूर्व मेयर रहे हैं, ने एनसीपी (SP) से इस्तीफा देकर कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। यह औपचारिक प्रवेश मुंबई के कांग्रेस मुख्यालय में राज्य कांग्रेस प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुआ। जगताप ने कहा कि वे वैचारिक लड़ाई के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं और भाजपा के विरोध में कांग्रेस की भूमिका को मजबूत करना चाहते हैं।

जगताप के कदम के पीछे एनसीपी (SP) के संभावित गठबंधन और पुणे-पिंपरी-चिंचवड में पार्टी के रणनीतिक फैसलों को लेकर उनके

मतभेद बताए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप उन्होंने लगभग 26 वर्षों बाद अपने पुराने राजनीतिक घर को छोड़ दिया।

विश्लेषकों के अनुसार, इस फैसले से कांग्रेस को पुणे और पश्चिम महाराष्ट्र में मजबूती मिलने की संभावनाएं बढ़ी हैं, विशेषकर जब आगामी नगरपालिकाओं के चुनावों में बड़ी मुक़ाबला अपेक्षित है। कांग्रेस नेताओं ने जगताप के शामिल होने का स्वागत किया है और इसे पार्टी की राजनीतिक ताकत में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है।

यह बदलाव महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को और अधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक बना सकता है, क्योंकि चुनावी समीकरण में नए गठबंधनों और उम्मीदवारों की संभावनाओं पर अब नई चर्चा शुरू हो गई है।



छत्रपती संभाजीनगर: नगर निगम चुनावों से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) के भीतर गंभीर कलह सामने आया है, जब पार्टी के ही नाराज़ गुट के समर्थकों ने अधिकृत उम्मीदवार की रैली पर हमला कर दिया। पार्टी ने महापालिका चुनाव के लिए दो दिन पहले आठ उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष फैल गया था।

घटना शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे वार्ड नंबर 12 के किराडपुरा क्षेत्र में हुई, जब आधिकारिक उम्मीदवार अपनी रैली निकाल रहे थे। रैली राम मंदिर रोड की ओर बढ़ रही थी, तभी एक पूर्व पार्षद के समर्थक अचानक वहाँ पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने रैली में

अड़ंगा डालते हुए आधिकारिक प्रत्याशी और समर्थकों के साथ हाथापाई की। समर्थकों ने उमेदवार को चेतावनी भी दी कि अगर पार्टी ने उनकी उम्मीदवारी पर पुनर्विचार नहीं किया, तो किराडपुरा क्षेत्र से एमआईएम का नामोनिशान मिटा देंगे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हंगामा इतनी तेज़ी से बढ़ा कि उम्मीदवार को अपने समर्थकों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर भागना पड़ा। इस विवाद के बाद इलाके में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही जिन्सी पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के आंतरिक झगड़े से एमआईएम की चुनावी रणनीति और एकता प्रभावित हो सकती है, खासकर जब अन्य पार्टियाँ भी स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। इस विवाद ने यह संकेत दिया है कि टिकट बंटवारा केवल चुनौती नहीं, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता-स्तर पर विद्रोह का कारण भी बन सकता है।



सांसद व NCP (शरद पवार) प्रमुख

पुणे में शरद पवार की शिवसेना (UBT) और कांग्रेस के साथ बैठक: MVA गठबंधन को नई दिशा देने की कोशिश

पुणे (महाराष्ट्र) - आगामी नगरपालिका चुनावों से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ देखने को मिला है, जहाँ राष्ट्रीय लोक सभा सांसद व NCP प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना (उद्धव ठाकरे समूह) और कांग्रेस के नेताओं के साथ एक होटल में अहम बैठक की।

बैठक का आयोजन पुणे के एक प्रतिष्ठित होटल में किया गया था, जिसमें तीनों दलों के प्रतिनिधियों ने सेट सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक का मकसद महाविकास आघाड़ी (MVA) को स्थानीय निकायों खासकर पुणे और बीएमसी चुनावों के लिए एकजुट करना

बताया जा रहा है। शरद पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) तथा कांग्रेस के बीच सीटों के विभाजन को लेकर अभी भी विचार-विमर्श जारी है।

सूत्रों के मुताबिक, ऐजित पवार के पक्ष के साथ पिछली बातचीत के बाद यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पहले दोनों NCP समूहों के बीच सेट वितरण पर असहमति बनी थी, जिसके कारण गठबंधन की संभावनाओं पर संकट भी उत्पन्न हुआ था।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस बैठक में यदि तीनों दल आर्थिक तथा

नागपुर: आगामी नागपुर महानगरपालिका चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन में बड़ी तेजी दिखाई है। मुंबई में गुरुवार को हुई प्रदेश चयन समिति की बैठक में कुल 125 से अधिक सीटों पर कांग्रेस के टिकट अंतिम रूप से तय कर दिए गए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, पृथ्वीराज चव्हाण, सतेज पाटील, प्रणिति शिंदे, विजय वडेहीवार, यशोमती ठाकूर तथा नागपुर प्रभारी रणजित कांबळे समेत वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

कई सीटों पर टिकट वितरण के दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीच प्राथमिकता जैसे विषयों पर कुछ असहमति बनी है, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। कुछ सीटों पर महिला व पुरुष उम्मीदवारों में संतुलन के लिए अतिरिक्त विचार

है। अब कांग्रेस जल्द ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकां) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने पर चर्चा करेगी। अंतिम निर्णय और सीटों का विवरण 27 दिसंबर को होने वाली बैठक में तय किया जाएगा।

यह कदम कांग्रेस की चुनावी तैयारी को मुकम्मल करने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि नागपुर मनपा चुनाव में पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है।

सामाजिक मुद्दों पर सहमति बना लेते हैं, तो MVA आगामी चुनावों में बीजेपी तथा अन्य प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मजबूत मोर्चा तैयार कर सकता है। वहीं, सीट बंटवारे में संतुलन और उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंतिम निर्णय अभी बाकी है और इस पर आगे की बैठकें होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान बातचीत में राजनीतिक रणनीति, युवा मतदाताओं को आकर्षित करना, स्थानीय विकास कार्यों की प्राथमिकता जैसे मुद्दों पर भी विचार हुआ। आगामी चुनाव परिणाम महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं।





स्वाधिकारी नंदिग्राम टाईम्स (नांटेड) के मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक शेख जहूर शेख अहेमद द्वारा सहारा डिजाइनिंग एंड ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, वाजेगांव, ता. व जि. नांटेड में मुद्रित तथा दैनिक नंदिग्राम टाईम्स, मुल्लाह मार्केट, खवी बिल्डिंग, नगेश्वर मंदिर, नांटेड-431604 (महाराष्ट्र) के कार्यालय से प्रकाशित। RNI-MAHHIN/2016/69743 मोबाइल संपर्क: 9921100075 | Email: ntinfodesk@gmail.com (वाद-विवाद हेतु न्यायक्षेत्र: नांटेड न्याय कक्षा में।)